***Date*:** 06-07-2021
***Publication*:** The Times of India
***Edition*:** Kolkata

Rule rejig: Coal India sends 1st rake to B'desh

Kolkata: In less than a month of Coal India (CIL) tweaking its e-auction coal sales policy, lifting the restriction on exports of its coal procured by domestic coal purchasers under two e-auction windows, the first coal-laden rake left for Bangladesh on July 2. One rake of coal weighs around 4,000 tonne.

The destination of below 2200 gross calorific value coal purchased under spot e-auction from Dahibari siding of Bharat Coking Coal (BCCL), the Jharkhand-based coal producing subsidiary of CIL, is Rampal Power Station, Khulna, Bangladesh.

This falls under Maitree Super Thermal Power Project — a joint venture between the Indian power producer NTPC and Bangladesh Power Development Board. The Bangladesh-bound coal left the Indian shore from Kolkata port.

Effective June 8, the Maharatana coal miner amended its e-auction sales policy allowing across-the-border sale of coal bought under spot e-auction and special spot e-auction by domestic coal purchasers, including traders. TNN

***Date*:** 06-07-2021
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Ranchi

कोल इंडिया ने पहली बार निर्यात किया कोयला

- **बांग्लादेश को भेजा 4000 टन कोयला**

एजेंसियां ▷ नयी दिल्ली

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने सोमवार को कहा कि पिछले सप्ताह करीब 4,000 टन कोयले से लदा रैक बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ. खरीदारों को कोयले के निर्यात की घरेलू कंपनी से मिली अनुमति के बाद यह पहली खेप है. इस ईंधन की खरीद पिछले महीने इ-नीलामी के जरिये घरेलू खरीदारों ने की. कोल इंडिया ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने पिछले महीने इ-नीलामी कोयला बिक्री नीति में बदलाव किया. इसके तहत दो इ-नीलामी व्यवस्था में घरेलू कोयला खरीदारों पर उससे खरीदे गये कोयले के निर्यात पर से पाबंदी हटा ली गयी. इसके तहत कोयले से लदा पहला रैक दो जुलाई को बांग्लादेश के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (कोलकाता) से रवाना हुई. नीति में संशोधन के बाद पहली बार कोयले का निर्यात हुआ है.

कोल इंडिया की झारखंड स्थित अनुषंगी इकाई बीसीसीएल से इ-नीलामी के जरिये खरीदा गया कोयला बांग्लादेश के खुलना स्थित रामपल बिजली घर के लिए भेजा गया है.

***Date*:** 06-07-2021
***Publication*:** Dainik Bhaskar
***Edition*:** Ranchi

कोल इंडिया का पांच वर्षों में 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य

राजीव कुकरेजा | रांची

कोल इंडिया ने अपनी खदानों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजना तैयार की है। अपने प्रतिष्ठानों में 5000 पारंपरिक एसी और अन्य उपकरणों की जगह स्टार रेटेड उपकरण लगाएगी। अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य है। कंपनी को इस वर्ष के अंत तक 60000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी की उम्मीद है। इसी तरह ऊर्जा की बचत के लिए परंपरागत लाइटों की जगह करीब ढाई लाख एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। कार्यालयों में पुराने पंखों को बदलकर उनकी जगह एक लाख से अधिक ऊर्जा के मामले में दक्ष पंखों का उपयोग किया जाएगा। कोयला कंपनियों की कॉलोनियों में बिजली बचाने के लिए 2200 स्ट्रीट लाइटों में ऑटो टाइमर लगाए जाएंगे। एचईएमएम उपकरणों को डीजल की जगह एलएनजी से संचालित किया जाएगा। इससे लागत में कटौती और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

***Date*:** 08-07-2021
***Publication*:** Dainik Jagran
***Edition*:** Dhanbad

कोल इंडिया ने 10 करोड़ की दी स्वीकृति

जासं, धनबाद : ऊर्जा और खनन के क्षेत्र में आइआइटी आइएसएम और कोल इंडिया मिलकर शोध करेंगे। उर्जा और खनन के क्षेत्र में दोनों संस्थानों का एक साथ मिलकर काम करना कई चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित होगी। कोल इंडिया खनन के क्षेत्र में आइआइटी आइएसएम के साथ मिलकर सेंटर फार इनोवेशन एंड इक्यूवेशन की स्थापना करने जा रहा है। आइआइटी आइएसएम ने सेंटर फार इनोवेशन एंड इक्यूवेशन के लिए 10 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, जिसे कोल इंडिया ने मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया मुख्यालय स्तर से प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों संस्थानों के बीच एमओयू होना है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही एमओयू की भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शुरूआती दौर में दोनों संस्थानों के बीच यह पांच प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

एमओयू जल्द

- दोनों संस्थानों के बीच पांच प्रोजेक्टों पर होगा काम
- ऊर्जा के क्षेत्र में खनन के दूसरे विकल्पों पर होगा शोध

ऊर्जा और खनन के क्षेत्र में होगा शोध : कोल इंडिया और आइएसएम के द्वारा स्थापित होने वाले सेंटर फार इनोवेशन एंड इक्यूवेशन सेंटर में छात्र और शिक्षक एनर्जी और माइनिंग क्षेत्र में न केवल रिसर्च करेंगे, बल्कि इस क्षेत्र में आने वाले चुनौतियों का समाधान भी ढूंढेंगे। यही नहीं भविष्य में ऊर्जा और खनन के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या-क्या बदलाव लाया जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में खनन के अन्य विकल्पों पर शोध किया जाएगा। आइआइटी आइएसएम में पहले से मौजूद नरेश वशिष्ठ टिंकरिंग एंड इनोवेशन लैब और माइनिंग हब का सबसे अधिक लाभ कोल इंडिया के सेंटर फार इनोवेशन एंड इक्यूवेशन को मिलेगा। पूरे देश में आइएसएम एक मात्र ऐसा संस्थान है, जिसे माइनिंग हब के लिए चयनित किया गया है। 200 करोड़ रुपये का फंड भी मुहैया कराया गया है।

***Date*:** 09-07-2021
***Publication*:** The Financial Express
***Edition*:** Bengaluru

CIL inks ₹1,462-cr pact with Russian shovel co

FE BUREAU
Kolkata, July 8

PSU MINER COAL India (CIL) has entered into a contract with Iz-Kartex, named after P G Korbokov, a Russian shovel manufacturing company, for installation and commissioning of 11 electric rope shovels valued at ₹1,462 crore. The Russian shovel manufacturer bagged the bid through participation in global tender involving reverse auction. Each rope shovels are 20 cubic metres in size.

The contract has been made for 8 years considering the life cycle cost of equipment with likely consumables and spares, a CIL executive said adding, the company was fast tracking its procurement process to strengthen its mining equipment base and replace the aging machines.

The delivery of all the electric rope shovels, to be used in open cast mines for overburden removal, would be concluded by September 2023.

All the eleven rope shovels would be used in the open cast projects of Northern Coalfields (NCL), which will swell the number of such equipment deployed in NCL mines from 9 to 20. The first, newly contracted machine, will roll out in NCL on June 2022 and thereafter at least one each every 45 days, the CIL executive said.

***Date*:** 10-07-2021
***Publication*:** Hari Bhoomi
***Edition*:** Korba

वर्ष 2023-2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य

कोलइंडिया दो वर्षों में 5 सौ परियोजनाओं में करेगी 1.22 लाख करोड़ का निवेश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कोरबा

कोलइंडिया ने देश में आधारभूत संरचना, कोयला निकासी, परियोजना विकास, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और अन्वेषण से संबंधित लगभग 500 परियोजनाओं के विकास के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपये रुपये से अधिक का निवेश करने का फैसला किया है।

खास बात

- कोलइंडिया को वर्ष 2023-24 तक एग मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य करना है हासिल

राष्ट्रीय खनिक संस्थान द्वारा निवेश का प्रमुख लक्ष्य भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वर्ष 2023-2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। इस निवेश का प्रमुख लक्ष्य भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वर्ष 2023-2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है।

फाइल फोटो

कोयला खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हितधारकों की बैठक को संबोधित करते हुए यह बताया कि कंपनी के मामलों में सभी हितधारकों की भागीदारी इस परियोजना के जोखिमों को उजागर और कम करेगी। कोल इंडिया लिमिटेड ने ऐसी 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की भी पहचान की है जो माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल के तहत संचालित की जाएंगी। इस क्रम से कुल मिलाकर 34 हजार 600 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस बैठक में कोल इंडिया ने हितधारकों की अधिक भागीदारी के लिए रियायत और छूट के उपायों की भी घोषणा की है। खनन निविदाओं के लिए अनुभव मानदंड को 65 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कम किया गया है जबकि टर्नकी अनुबंधों के लिए कार्य अनुभव मानदंड में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

दो चरणों में 14 हजार 200 करोड़ का निवेश

राष्ट्रीय खनिक, कोल इंडिया लिमिटेड अगले 3 से 4 साल में 49 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए दो चरणों में लगभग 14 हजार 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में पिटहेड्स से डिस्पैच पॉइंट तक कोयले का परिवहन किया जाएगा, सड़क के माध्यम से परिवहन की मौजूदा पद्धति को बदलने के लिए कोयले की कंप्यूटर एडेड लोडिंग तकनीक भी विकसित की गई है, कोलइंडिया वर्ष 2023 24 तक कुल 1.22 लाख करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि में से खान अवसंरचना पर 25 हजार 117 करोड़ रुपये, कोयला निकासी पर 32 हजार 696 करोड़ रुपये और परियोजना के विकास पर 29 हजार 461 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है।

***Date*:** 11-07-2021
***Publication*:** Sanmarg
***Edition*:** Asansol

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने दिया जोर

सांकतोड़िया : कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन ने ऊर्जा दक्षता से जुड़े उपायों पर विशेष जोर दिया है। साथ ही अपनी सभी कोयला उत्पादक कंपनियों के खनन कार्यों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपायों की एक श्रृंखला के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोल इंडिया सूत्रों ने बताया कि कोल इंडिया ने ऊर्जा दक्षता के उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से अगले पांच वर्षों में लगभग 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन

▪ एलएनजी को टर्मिनल से खदान तक ले जाने की व्यवस्था करेगा और किट एवं रेट्रोफिटिंग की व्यवस्था करेगा।

में कमी लाने की परिकल्पना की है। कोल इंडिया सभी मोर्चों पर सक्रिय कार्यान्वयन के जरिए इस वर्ष के अंत तक 60000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता होगी। कोल इंडिया प्रबंधन ने कुछ खदानों में गेल के सहयोग से पायलट परियोजना शुरू करने की पहल की है। इस परियोजना के तहत गेल एलएनजी भंडारण और वितरण प्रणाली स्थापित करेगा। एलएनजी को टर्मिनल से खदान तक ले जाने की व्यवस्था करेगा और किट एवं रेट्रोफिटिंग की व्यवस्था करेगा। इस काम के लिए बीईएमएल सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। कोल इंडिया प्रबंधन अपने सभी खनन कार्यों में पंपों के लिए ऊर्जा के मामले में दक्ष लगभग 1700 मोटरों का उपयोग शुरू करेगा। विभिन्न प्रतिष्ठानों में लगभग 5000 पारंपरिक एसी और अन्य उपकरणों की जगह ऊर्जा के मामले में दक्ष स्टार रेटेड उपकरण लगाएगा। इसी तरह ऊर्जा की बचत करने के लिए परंपरागत लाइटों के स्थान पर करीब ढाई लाख एलईडी लाइटें लगाई जायेंगी। कार्यालयों में पुराने पंखों को बदलकर उनकी जगह 1 लाख से अधिक ऊर्जा के मामले में दक्ष पंखों का उपयोग किया जाएगा। कॉलोनियों में बिजली बचाने के लिए करीब 2200 स्ट्रीट लाइटों में ऑटो टाइमर लगाए जायेंगे। कमिंस के सहयोग से पूरी पायलट अवधि के दौरान डम्पर और इंजन के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी और उसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया द्वारा विभागीय स्तर पर या संविदात्मक रूप से चल रहे एचईएमएम उपकरणों के विशाल बेड़े में बदलाव लाकर उन्हें डीजल की जगह एलएनजी से संचालित करने पर है। यह न केवल लागत में कटौती करने की दिशा में एक बड़ी सफलता होगी, बल्कि इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए तत्काल उपाय करने के अलावा कोल इंडिया ने अपने काम-काज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की एक महत्वाकांक्षी पांच-वर्षीय योजना भी तैयार की है। इन कोयला कंपनियों ने विद्युत आपूर्ति के कुशल प्रबंधन के अलावा ऊर्जा दक्षता के उपायों को कालोनियों, भवनों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि जैसे कई क्षेत्रों में लागू किया है। हालांकि कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी कमी हेवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम), परिवहन, वेंटिलेशन, पंपिंग आदि जैसे खनन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। सीआईएल वर्षों से अपनी सहायक कंपनियों की मदद से ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के विभिन्न उपाय करता आ रहा है और अब वह अधिक पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गतिविधियों पर ध्यान देते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्य जोर सीआईएल ने एलएनजी का थोक उपयोग शुरू करने से पहले सीआईएल के कुछ खदानों में गेल के सहयोग से पायलट परियोजना शुरू करने की पहल की है। इस परियोजना के तहत गेल एलएनजी भंडारण और वितरण प्रणाली स्थापित करेगा। एलएनजी को टर्मिनल से खदान तक ले जाने की व्यवस्था करेगा और किट एवं रेट्रोफिटिंग की व्यवस्था करेगा। इस काम के लिए बीईएमएल सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। कमिंस के सहयोग से पूरी पायलट अवधि के दौरान डम्पर और इंजन के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी और उसका अध्ययन किया जाएगा।